

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2024—कार्तिक 10, शक 1946

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 अक्टूबर 2024

क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन तथा पुनर्वास विभाग तथा अति. प्रभार पदेन राहत एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त भू-अभिलेख को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री अन्बलगन पी. भा.प्र.से. (2004), सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा अति. प्रभार सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव, जनशिकायत निवारण विभाग को केवल सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है। शेष प्रभार यथावत् रहेगा।
  3. श्री टोपेश्वर वर्मा, भा.प्र.से. (2005), सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करते हुए अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
  4. श्री के. डी. कुंजाम, भा.प्र.से. (2009), विशेष सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए विशेष सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग एवं संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
  5. श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख, संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, विशेष सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, प्रबंध संचालक, मार्कफेड को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड के पद पर पदस्थ करता है।
- श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. द्वारा प्रबंध संचालक, मार्कफेड का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत प्रबंध संचालक, मार्कफेड के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
6. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ प्रबंध संचालक, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
  7. श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. (2013), संयुक्त सचिव, मंत्रालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, भू-अभिलेख के पद पर पदस्थ करते हुए संयुक्त सचिव, जनशिकायत एवं निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।
- श्री विनीत नंदनवार, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, भू-अभिलेख का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-12 के तहत संचालक, भू-अभिलेख के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।
8. डॉ. फरिहा आलम, भा.प्र.से. (2016), उप सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ उप सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकेश कुमार बंसल, सचिव.

**राजस्व विभाग**

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2024

प्रारूप-एक  
(नियम-11 देखिये)

भू-अर्जन प्र. क्रमांक/19/अ-82/2022-23.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	नगर/ग्राम (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
बिलासपुर	बेलगहना	छतौना	0.951 हेक्टेयर	छतौना जलाशय योजना नहर निर्माण (पूरक प्रकरण)
उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 15-10-2024 को (समय) 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन, ग्राम छतौना पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—				
(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	छतौना जलाशय योजना नहर निर्माण (पूरक प्रकरण)	
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—	
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	—	
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक	
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक	
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां	
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	छतौना जलाशय योजना नहर निर्माण (पूरक प्रकरण)	
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3841.79 लाख	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	खरीफ सिंचाई सुविधा का विस्तार	
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	भूमि अर्जन पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु दल का गठन कर प्रस्तावित भूमि का सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया गया, जिसमें किसी व्यक्ति/कुटुम्बों का विस्थापन नहीं हो रहा है.	
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक	

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**अवनीश कुमार शरण,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मोहला मानपुर अं. चौकी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मोहला मानपुर अं. चौकी, दिनांक 25 सितम्बर 2024

प्रारूप-एक  
(नियम-11 देखिये)

क्रमांक/10259/भू-अर्जन/2024.— भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/कृषकों की संख्या (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
मोहला-मानपुर- अं. चौकी	खड़गांव	सरोली प.ह.नं. 02/ कृषकों की संख्या-04	0.065 हे.	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि. राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग के अनुसार ग्राम सरोली की भूमि, बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खड़गांव मार्ग पर उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत ग्राम सरोली की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 25-10-2024 को समय 11.00 बजे स्थान .....पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग. राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना लो.नि.वि. राजनांदगांव मुख्यालय दुर्ग के अनुसार ग्राम सरोली की भूमि, बिहरीकला-दनगढ़-सोमाटोला-गोटाटोला-खड़गांव मार्ग पर उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण मार्ग चौड़ीकरण अंतर्गत ग्राम सरोली की भूमि का अधिग्रहण प्रकरण.
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में निजी शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	आवागमन में सुविधा
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय किए जा रहे हैं.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

सारंगढ़-बिलाईगढ़, दिनांक 4 अक्टूबर 2024

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202410320600027/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का वर्णन					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़	छतौना प.ह.नं. 37	0.438	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग क्रमांक 01, खरसिया जिला रायगढ़	साराडीह बैराज योजना हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**धर्मेंश कुमार साहू**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

कोण्डागांव, दिनांक 5 सितम्बर 2024

खसरा नम्बर  
(1)

रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

2/9

0.025

क्रमांक/5454/202206200900049/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-कोण्डागांव
  - (ख) तहसील-मर्दापाल
  - (ग) नगर/ग्राम-तोतर
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.050 हेक्टेयर

योग

02

0.050

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम-तोतर, तहसील मर्दापाल व्यपवर्तन अन्तर्गत आदनार-तोतर मार्ग के कि.मी. 1/6 भवरडींग नदी पर उच्चस्तरीय सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**कुणाल दुदावत**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-बस्तर, जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

जगदलपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2024

रा.प्र.क्र. 04/अ-74/2023-24  
ई-कोर्ट नंबर 202408150100026

आम जनता ग्राम राजूर प.ह.नं. 17 राजूर,  
रा.नि.मं. केशलूर, तहसील तोकापाल, जिला बस्तर (छ.ग.)

### विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

### आदेश

( पारित दिनांक 25/09/2024 )

क्रमांक/क/रीडर/202408150100026/अ-74/2023-24.—ग्राम पंचायत राजूर से नवीन ग्राम पंचायत राजूर-2 एवं ग्राम पंचायत बेड़ागुड़ा पृथक किये जाने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल, जिला बस्तर के प्रतिवेदन पत्र क्र. 1106/अ.वि.अ.(रा)/2023-24, दिनांक 23-08-2024 के द्वारा मूल राजस्व ग्राम राजूर का पुनर्गठन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ. प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण दर्ज की जाकर जांच की कार्यवाही की गई. प्रकरण जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (रा) तोकापाल की अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ. प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों एवं प्रतिवेदन से वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :—

1. प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार मूल ग्राम राजूर एवं पुनर्गठित राजस्व ग्राम राजूर का विवरण निम्नानुसार है :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम राजूर की स्थिति		प्रस्तावित पुनर्गठित राजस्व ग्राम राजूर की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2533	1573.16	1355	800.56
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1938	987.65	980	471.77
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल				
अ	आबादी भूमि	41	5.17	19	1.49
ब	अमराई बाग	5	2.36	2	1.49
स	छोटे झाड़ के जंगल व घास	437	485.14	299	297.20
द	बड़े झाड़ के जंगल	1	4.00	0	0
ई	पानी के नीचे	18	10.15	8	5.51
फ	पहाड़ चट्टान	2	9.01	0	0
ज	सड़क व रास्ता	91	69.68	47	23.10
	योग	595	585.51	375	328.79

4.	कुल खातेदारों की संख्या	786	987.65	—	—
5.	कुल भू-राजस्व	—	2136.17 रु.	—	1020.42 रु.
6.	ग्राम की जनसंख्या	—	3961	—	1397 लगभग

- राजस्व ग्राम राजूर को पुनर्गठित करने हेतु ग्राम में उद्घोषणा का प्रकाशन दिनांक 29-08-2024 को कराया गया, जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ।
- ग्राम राजूर को पुनर्गठित करने हेतु ग्राम पंचायत राजूर, राजूर-2 द्वारा दिनांक 20-08-2024 एवं ग्राम पंचायत बेड़ागुड़ा द्वारा दिनांक 23-08-2024 को सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है।

प्रकरण की उपरोक्त स्थिति पर म.प्र. राजपत्र दिनांक 22 जनवरी 1960 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 177-6477-सात-ना(नियम), दिनांक 06 जनवरी, 1960 के तहत निर्मित नियम के परिप्रेक्ष्य में मनन करने से मेरा यह समाधान हो गया है कि,

- ग्राम राजूर के लिये पर्याप्त दखल रहित भूमियां हैं, जिसके कारण सामाजिक अधिकारों का उपभोग पृथक रूप से संचालित किया जाना सुविधाजनक होगा।
- ग्राम राजूर का क्षेत्रफल पृथक-पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने के लिये निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल 200 एकड़ से अधिक है।
- ग्राम राजूर का पुनर्गठन करने से ग्राम के आम जनता को समुचित सुविधा प्राप्त होगी।

अतएव मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील तोकापाल, रा.नि.मं. केशलूर, प.ह.नं. 17 स्थित राजस्व ग्राम राजूर को पुनर्गठित करने का आदेश पारित करता हूँ।

यह आदेश आगामी राजस्व वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगा। अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के जारी होने के बाद एक दल तैयार करके ग्राम का खसरा, क्रमांक-1 से प्रारंभ करके पुनरांकित कर लेवें तथा इसी प्रकार नक्शा सहित अन्य पटवारी अभिलेख भी अलग-अलग तैयार कर लेवें तत्पश्चात् पालन प्रतिवेदन देवें। इस आदेश की प्रतिलिपि छ.ग. राजपत्र में प्रकाशनार्थ भेजा जावे तथा सर्व संबंधितों की ओर उक्त ग्राम को पृथक ग्राम के रूप में अपने अभिलेख में अभिलिखित कर अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 25-09-2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायायलीन पदमुद्रा सहित पारित किया गया।

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3151/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील जगदलपुर, रा.नि.मं. फ्रेजरपुर प.ह.नं. 13 करकापाल अंतर्गत

स्थित राजस्व ग्राम बिलोरी को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम पोड़ागुड़ा के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम बिलोरी की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम बिलोरी की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम पोड़ागुड़ा की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	1630	1009.5	1053	531.63	577	477.87
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1374	591.5	904	362.43	470	229.07
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	7	7.05	5	2.84	2	4.21
ब	अमराई बाग	4	2.59	4	2.59	0	0
स	छोटे झाड़ के जंगल व घास भूमि	98	44.53	73	33.63	25	10.9
द	बड़े झाड़ के जंगल	70	308.33	22	98.92	48	209.41
ई	पानी के नीचे	27	30.24	15	18.45	12	11.79
फ	पहाड़ चट्टान	0	0	0	0	0	0
ज	सड़क व रास्ता	50	25.26	30	12.77	20	12.49
	योग	256	418.00	149	169.2	107	248.8

जगदलपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2024

क्रमांक/3153/कले./रीडर/2023-24.—एतद्वारा मैं हरिस. एस, कलेक्टर, जिला बस्तर (छ.ग.) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 70 एवं 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला बस्तर, तहसील करपावण्ड, रा.नि.मं. बकावण्ड प.ह.नं. 05 छिन्दागांव अंतर्गत स्थित राजस्व ग्राम छिन्दागांव को विभाजित करके निम्नानुसार ग्राम सिधावंड के रूप में राजस्व ग्राम घोषित करता हूँ :—

स. क्र.	मद का विवरण	वर्तमान राजस्व ग्राम छिन्दागांव की स्थिति		विभाजित करने पर			
				ग्राम छिन्दागांव की स्थिति		प्रस्तावित ग्राम सिधावंड की स्थिति	
		कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)	कुल खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भौगोलिक क्षेत्रफल	2612	2192.65	1169	1011.99	1443	1180.66
2.	मकबूजा क्षेत्रफल	1827	858.33	781	553.98	1046	304.35
3.	गैर मकबूजा क्षेत्रफल						
अ	आबादी भूमि	8	0.96	4	0.49	4	0.47
ब	अमराई बाग	2	1.31	0	0	2	1.31
स	छोटे झाड़ के जंगल व घास भूमि	276	188.00	134	89.76	142	98.24
द	बड़े झाड़ के जंगल	389	1054.00	193	327.13	196	726.87
ई	पानी के नीचे	36	50.45	24	21.05	12	29.40
फ	पहाड़ चट्टान	0	0	0	0	0	0
ज	सड़क व रास्ता	74	39.60	33	19.58	41	20.02
	योग	785	1334.32	388	458.01	397	876.31

( हरिस. एस )  
कलेक्टर.